आकाशवाणी केन्द्र शिमला

07.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

शानन परियोजना

राज्य सरकार शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर उच्चत न्यायालय का रूख करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में बताया कि जोगिन्द्रनगर में एक सौ 10 मैगावॉट की शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए उचित दावों को न्यायालय में पेश करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब सरकार को ये परियोजना हिमाचल को सौंपे जाने को लेकर आदेश जारी करने का आग्रह किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मामले को केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष भी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रदेश के न्याय संगत अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी जाई जाएगी और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईड्रो क्षेत्र में प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विद्युत परियोजनाओं में 12, 18 और 30 फीसदी रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया गया है जबकि 40 वर्ष बाद परियोजना को राज्य सरकार को सौंपे जाने का प्रावधान भी किया गया है।

समझौता ज्ञापन

प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शिमला में राज्य सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचलित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में आईएमडी द्वारा स्थापित 22 स्वचलित मौसम केंद्र क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम केंद्रों का यह तंत्र स्थापित होने से प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली और

आपातकालीन स्थितियों जैसे अत्याधिक वर्षा, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार की विस्तृत आपदा और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के लिए फ्रांस की एजेंसी एएफडी के साथ सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत एएफडी परियोजना के लिए 8 सौ 90 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कुशल प्रबंधन व हेलीपैड निर्मित करने के साथ–साथ आपदा प्रबंधन के लिए एक राज्य संस्थान की स्थापना की जाएगी और एक नई राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कंपनी का गठन भी किया जाएगा।

संजौली–मस्जिद

शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को फटकार लगाते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी। हिंदू संगठन के वकील जगत पाल ने आज शिमला में बताया कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके ये मस्जिद बनाई है। अदालत ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद की पांच मंजिले बनाने और इससे स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों के संबंध में भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जब अढ़ाई मंजिल मस्जिद का नक्शा पास था तो वह पांच मंजिला कैसे बन गई। वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह के मुताबिक उन्हें सिर्फ एक मंजिल के निर्माण की जानकारी है लेकिन मस्जिद की चार मंजिले बनाने की कोई जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबदीन का कहना है जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में सिर्फ एक मंजिल दर्ज है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्थानीय मस्जिद कमेटी को दरकिनार कर अवैध रूप से मस्जिद की चार और मंजिले बना दीं है।

गणेश चतुर्थी

देश सहित प्रदेश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं

स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान बप्पा की पूजा करते हैं और अंतिम दिन प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। इस दिन को विनायक चतुर्थी और गणेश उत्सव भी कहते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का जश्न मनाना है। पांच वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट पर दाखिल किए जा सकते हैं।

.....